मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- विकास का धंधा बना लूट का फ़ंदा
- मैट्रो रेल से रोडवेज घाटे में? 3
- ऐ वतन...तेरे खिलाफ साजिश हो रही है
- फासीवाद की चुनौती विकल्पहीनता का संकट 4
- खुद चोरी कराते हैं फिर चोर पकड़ने का नाटक
- एक घर जो बस न सका 5
- हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा, बजट केवल 3156 करोड़ 8

वर्ष 29 अंक 10 फरीदाबाद, शुक्रबार 1-15 अप्रैल 2016 फोन : - 9999595632 2 ₹

ध्रुवीकरण की चूहेदानी में फ़ंसी हरियाणा सरकार

न सुरक्षा न मुआवजा नसीब, आम जन को

हरियाणा को खट्टर शासन में आरक्षण हिंसा के दंश से उबरने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। 18 से 23 फ़रवरी के हिंसक तांडव के खौफ़ से न प्रदेश का आम जन सुरक्षित महसूस कर पा रहा है और न सरकार की साख ही ऐसी बची है जो उसे सुरक्षा का एहसास दिला सके। यहां तक कि मुआवज़ा देने की प्रक्रिया इतनी विषम बना दी गयी है कि घावों पर जो थोड़ा-बहुत मरहम लग सकता था, वह भी नहीं लग पा रहा। हिंसा प्रभावित शहरों में ऐसे तमाम लोग मिल जायेंगे जो सरकारी निर्भता की बजाय खुद की सुरक्षा तैयारी में जुटे रहना बेहतर विकल्प मानते हैं। क्या हरियाणा कहीं जातीय हिंसा के मुहाने पर तो नहीं खड़ा?

मज़दूर मोर्चा, रोहतक ब्यूरो

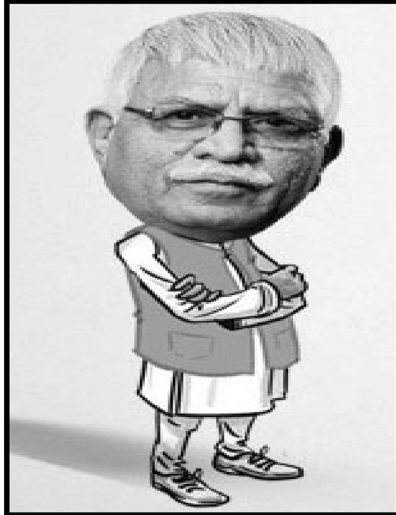

सरकार चलाने और आरएसएस चलाने में फर्क को समझो खट्टर साहब

आरक्षण हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित रोहतक शहर तनाव की चादर ओढे पसरा है। इस चादर को उतार कर अन्दर झांकने की क्षमता खट्टर शासन में नज़र नहीं आती। 'आरक्षण', ज्यों का त्यों ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है जिसका कोई सर्वमान्य समीकरण बन पाना एक टेढी खीर सिद्ध हो रहा है। इसके बरक्स 'मुआवज़ा' एक आसान रास्ता माना जा रहा था, जिसे भी धीमी प्रशासनिक चाल और पक्षपाती रवैये के हवाले कर दिया गया है।

19-20 फ़रवरी के दो दृष्य रोहतक निवासियों के मानस पटल पर अंकित हैं। डीजीपी बलजीत सिंह संधू के नेतृत्व में पुलिस और सैन्य बलों का फ्लैग मार्च, पुलिस लाइन से राजीव चौक पर धरना दिये बैठे आरक्षण आन्दोलनकारियों तक पहुंच कर, उनके पथराव के सामने वापस मुड़ने को मजबूर हुआ। इसके बाद पूरा शहर गुंडा तत्वों के हवाले हो गया और पुलिस नज़र आना बन्द हो गयी। इस अराजकता के बीच एक अकेला आदमी अपनी साइकिल पर तख्ती लगा कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता-जाता दिखाई पड़ा। उसकी तख्ती पर लिखा था। भाइयो कृप्या शान्ति बनाये रखें।

उस माहौल का यह सबसे करीबी शब्द-चित्र हो सकता है। शान्ति के तलबग़ार शहर निवासी और शान्ति बना पाने में असमर्थ शासन-प्रशासन! औपचारिक रूप से शहर कर्फ्यू के हवाले था पर वास्तव में वह गुंडों के हवाले था। सुखपुरा चौक, जहां सैनियों की दर्जनों दुकानें लूटी गयीं व आग के हवाले की गयीं, से गोहाना को जाने वाली सड़क पर तीन प्रमुख निजी स्कूलों को एक ही दिन में दो बार भीड़ का निशाना बनना पड़ा। तीनों के मालिक पंजाबी समुदाय से हैं। रात के अन्तिम पहर में 3-4 ट्रालियों में आये लोगों ने पत्थराव और आगज़नी की। 10-12 घंटे के बाद एक बड़ी भीड़ ने पुन: आकर इन्हीं स्कूलों में जम कर तोड़-फ़ोड़ मचाई। इस दौरान बार-बार बुलाने पर भी पुलिस ने दर्शन नहीं दिये।

हिंसा का यही ख़ाका जगह-जगह देखने को मिला। इस दौरान 7 लोग मारे गये जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो सर्किट हाउस पर डीआईजी पुलिस सौरभ सिंह पर हुए हमले को विफ़ल करने में बीएसएफ़ की गोली का शिकार बने। एक भी मौत लूट या नागरिकों के विरुद्ध हिंसा को थामने में नहीं हुई।

उत्तेजित आन्दोलनकारी और हिंसा का नेतृत्व करने वालों के बीच भी फ़र्क देखा जा सकता था। मोटर साइकिलों पर नकाबपोश तीन-तीन युवाओं को आगजनी और लूट-मार करते देखा गया। जिस तेज़ी से वे आग लगाने और उत्तेजना भड़काने का काम कर रहे थे, लगता था कि किसी ने उनका एजेंडा तय किया हुआ था। उंगली हर दिशा में उठाई जा रही है-चौटाले, हुड्डे, भाजपाई!

हिंसा का दौर स्वत: थम जाने के बाद प्रशासन के पास अपनी साख बचाने का एक और मौका था, मुआवज़ा तेज़ी से और बिना किसी पक्षपात के वितरित करके। इसमें भी असफ़लता की वही पहले वाली कहानी दोहराई गयी है। छोटे-छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बीमा, वैट, आयकर और पुरानी रसीदों के झमेलों में उलझा दिया गया है। संस्थाओं से, जिनका रिकार्ड जल गया, खरीद-फ़रोख्त के पुराने काग़ज़ात मांगे जा रहे हैं। औसतन 10 से 20 प्रतिशत तक ही मुआवज़ा दिया गया है।

आरक्षण के दायरे में विभिन्न दावेदारों के बीच संतुलन बैठाने के लिये खट्टर सरकार के पास महज 3 प्रतिशत सीटें ही इधर-उधर करने को हैं। सैनी समेत पहले से आरक्षित जातियां जाटों को अपने घेरे में इस डर से नहीं आने देना चाहती कि सारे फ़ायदे वे हड़प जायेंगे। दूसरी तरफ़ जाट 10 प्रतिशत से कम आरक्षण से कम पर राज़ी होने वाले नहीं। खट्टर सरकार चाहे जितनी जोड़-तोड़ करले संभावना यही है कि कोई भी फ़ार्मूला सभी पक्षों को असन्तुष्ट ही करेगा।

एक अकर्मण्य एवं दिशाहीन शासन के सामने अनिश्चित भविष्य मुंह बाये खड़ा है। ऐसे में यदि हरियाणा को हिंसा का एक और दौर देखना पड़ा तो वह अधिक लोमहर्षक और समाज- विभाजक सिद्ध होगा। तब राजनीतिक जवाबदेही की लपेट में आने से प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं बच सकेंगे।

ख़बर दार

तेरा क्या होगा रे अमितशाह!

तेरा क्या होगा रे अमितशाह! इस अप्रैल-मई में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। तमिल नाडु, केरल, बंगाल, असम और पांडिचेरी। इनमें खासकर असम और बंगाल में भाजपा अध्यक्ष अमितशाह ने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रखी है। बंगाल में सारदा चिट फंड स्कैम की आड़ में सीबीआई की मार्फ़त तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बढाया गया है जबकि असम में तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैंठियों का मुद्दा उठा कर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का रास्ता पकड़ा गया है। घूम-फ़िर का धौंस और धर्म की पतवार से चुनावी नैया खेने में जुटे अमितशाह से मज़दूर मोर्चा ने काल्पनिक साक्षात्कार किया।

म.मो.-सभी जानते हैं कि तमिलनाडु और केरल में भाजपा का कोई चांस नहीं है। अब यदि अमित शाह जी आपके नेतृत्व में पार्टी असम और बंगाल में भी पिट गयी तो आपका क्या होगा? क्या मोदी विरोधी ग्रुप आपकी छुट्टी कराने की मुहिम नहीं छेड़ेगा?

अमित शाह-मुझे सीबीआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पूरा भरोसा है कि वे क्रमश: बंगाल और असम में हमारी नैया पार लगा देंगे। रही हार की बात तो दिल्ली और बिहार मेरे नेतृत्व में पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। मोदी जी का वरदहस्त मेरे सिर पर है, मुझे हार-जीत से क्या फ़र्क पड़ता है।

म.मो.-क्या आपको नहीं लगता कि एक और करारी हार के बाद मोदी जी पर आपको हटाने का दबाव बढ जायेगा जिसे वे शायद ही सह सकें?

अमित शाह-क्या गुजरात नरसंहार का दबाव कम था? क्या महिला आर्किटेक्ट की जासूसी उज़ागर होने का दबाव कम था? क्या इशरत जहां जैसी तमाम झूठी मुठभेड़ों का दबाव कम था? क्या आडवाणी खेमे का दबाव कम था? राज़दारों के बीच के रिश्ते बड़े गाढ़े होते हैं। तो यह तो भूल ही जाओ कि मोदी जी किसी दबाव में मुझे पद से हटाने की सोचेंगे भी। हद से हद यह हो सकता है कि मुझे वे भारत का अगला राष्ट्रपति बेशक बना दें और तब मैं भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ दूं।

म.मो.-असम और बंगाल में आपकी जीत के मायने क्या होंगे? लगे हाथ यह भी बता दीजिये कि इन दोनों राज्यों में आपकी हार के मायने क्या होंगे?

अमित शाह-जीत के मायने तो स्पष्ट हैं-विकास का जुमला गया भाड़ में, राज करेंगे सीबीआई और हिन्दुत्व के सहारे। रही हार की बात तो इसका दोष बंगाल में ममता के सिर और असम में कांग्रेस की छद्म धर्म-निर्पेक्षता के मत्थे मढ देंगे।

म.मो.-अमित जी आपको शर्म बिल्कुल नहीं आयेगी? मोदी के मुकाबले बंगाल की जनता ममता को चुनने जा रही है। असम जैसी 15 साल से चल रही भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार तक आपके मुकाबले में जीतने की उम्मीद के साथ मैदान में उतर रही है। क्या इतनी जल्दी मोदी का जादू उतर गया? तमिल नाडु और केरल में लाख जोड़-तोड़ के बावजूद आप लोग कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं?

अमित शाह-भई गुजरात मॉडल का यही फ़साना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में खूब चला था। आज नहीं तो कल फ़िर से चलना शुरू होगा, ऐसी उम्मीद के दम पर मैं और मोदी जी चुनावी सभाओं में मुस्कराते नज़र आते हैं। अगर कहीं अब सारे राज्यों में हार भी गये तो अरूणाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला मॉडल अपना लेंगे। यानी उठा-पटक व खरीद-फ़रोख्त कर राष्ट्रपति शासन लगाओ और अपनी सरकार चलाओ।

काला धन तो क्या लायेंगे, सफ़ेद भी हुआ उड़नछू

यह कोई राष्ट्रवादी पहेली नहीं कि मोदी-जेटली ने ज़ालसाज़ कार्पोरेट विजय माल्या को 9000 करोड़ डकार कर देश से भागने क्यों दिया? देखा जाय तो मोदी-जेटली ने अपने चुनावी घोषणापत्र के मुताबिक ही काम किया। आखिर उनका वादा काला धन विदेश से वापस लाने का था न कि देश से बाहर जा रहे सफ़ेद धन को रोकने का।

माल्या द्वारा डकारी गयी सारी रकम उसे बैंकों से हासिल हुई थी। यानी कि यह सारा धन सफ़ेद ही तो था। ऐसे में भला बेचारे मोदी-जेटली इसमें क्या कर पाते! उन्हें तो भाजपा ने काला धन लाने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वे अपना ध्यान सफ़ेद धन की ओर क्योंकर लगाते? यानी मोदी-जेटली को नाहक ही बदनाम किया जा रहा है।

आइये समझें काले और सफ़ेद धन के आदान-प्रदान में वास्तव में हो क्या रहा है। देश में निरंतर पैदा हो रहा हज़ारों-लाखों-करोड़ का काला धन विदेशों में जाकर सफ़ेद हो जाता है। अब इसका निवेश भारत में ही किसी न किसी रूप में होने लगता है। इसी तरह देश से सफ़ेद धन हड़पने के लिये उसे बाहर ऐसे देशों में ले जाया जाता है जहां कोई सवाल-जवाब नहीं होता। वहां यह काले धन के रूप में सुरक्षित छिपा रहता है और अनुकूल समय पाकर सफ़ेद धन के रूप में भारत लौटता रहता है।

यह कोई अकेला मोदी-जेटली का शुरू किया हुआ खेल नहीं है। लेकिन माल्या के पलायन से मोदी सरकार कटघरे में जरूर आ गयी है। काले धन को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले रामदेव को भी माल्या मुद्दे पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं लगती होगी। आखिर रामदेव भी 'सफ़ेद धन' पर क्यों बोले? वैसे तो इस भगवा व्यापारी ने फ़िलहाल काले धन पर भी बोलना बंद कर रखा है। कुछ तो मोदी के नाराज होने का डर है और कुछ अपनी ज़मीर भी कचोटती होगी। जब स्वयं का लक्ष्य ही कच्ची धानी का तेल तक बेचना रह गया हो तो काले धन से कैसा परहेज?